and Bhopal Slum Clearance projects are being modified. The question of granting Central assistance for these projects will be considered on the receipt of further proposals from the State Government.

Fertilizer Factory in Rajasthan

*183. **Dr. Ram Subhag Singh:**
Shri Rameshwar Tantia:
Shri Wodeyar:
Shri Daljit Singh:
Shri N. M. Deb:

Will the Minister of **Commerce and Industry** be pleased to state:

(a) whether Government have invited proposals for setting up a fertilizer factory at Hanumangarh in Rajasthan; and

(b) by what time Government expect that the fertilizer factory will be set up there?

The Deputy Minister of Commerce and Industry (Shri Satish Chandra): (a) Yes, Sir.

(b) It is difficult to be precise at this stage.

संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में भारतीय

*१८४. **श्री पद्म देव :**
श्री कोडियान :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र सचिवालय और इसके प्रमुख अभिकरणों में कितने भारतीय राष्ट्रजन काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनकी नियुक्तियां किस प्रकार की जाती हैं ?

विदेश उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) : (क) ३१ अगस्त, १९६० को संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में व्यावसायिक स्तर (प्रोफेशनल लेवल) की और इससे ऊंची जगहों पर ६१ भारतीय राष्ट्रिक काम कर रहे थे । संयुक्त राष्ट्र की विभिन्न विशिष्ट ऐजेंसियों (स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़) में जिन जिन जगहों पर भारतीय राष्ट्रिक काम कर रहे हैं, उनके बारे में में विभिन्न मंत्रालयों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और जहां तक होगा, वह सूचना जल्दी ही दे दी जाएगी ।

(ख) आम तौर से, संयुक्त राष्ट्र का कर्मचारी कार्यालय (ब्यूरो आफ परसानेल) विभिन्न लोगों से प्राप्त दरखास्तों का लेखा-जोखा रखता है और जगहें खाली होने पर उचित लोगों को भर्ती करने की कोशिश करता है । जहां तक व्यावहारिक होता है, लोगों को प्रतियोगिता के आधार पर चुना जाता है ; और ऐसा करते समय इस बात का समुचित ध्यान रखा जाता है कि जहां तक संभव हो, कर्मचारी व्यापक भौगोलिक आधार पर भर्ती किए जायं ।

मूल्य सूचियां लगाना

*१८५. **श्री सरजू पांडे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने राज्य सरकारों को एक परिपत्र के द्वारा यह सुझाव दिया है कि सब दुकानों पर वस्तुओं की मूल्य सूचियां लटकाई जानी चाहिएं ; और

(ख) यदि हां, इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रियाएं हुई हैं ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी हां ।

(ख) यह इत्तला हासिल नहीं है क्योंकि प्रधान मंत्री ने राज्य सरकारों से यह इत्तला नहीं मांगी थी ।